भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2343

09 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

असम में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं

2343. श्री कृपानाथ मल्लाह:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान मंजूर की गई खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण तथा अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान असम हेतु सरकार ने कोई धनराशि मंजूर की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के अंतर्गत 'मिनी फूड पार्क' को भी शामिल किया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र वृद्धि और विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है । पीएमकेएसवाई की घटक योजनाएं मांग आधारित हैं, जिसके तहत अनुदान सहायता के रूप में क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), उद्यमियों, सहकारी समितियों, समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), निजी कंपनियों और केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि को प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना के सृजन के लिए और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की देश भर में (असम राज्य सहित) स्थापना के लिए प्रदान की जाती है और पृथक राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है ।

मंत्रालय ने अभी तक पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 1 मेगा फूड पार्क परियोजना, 2 परियोजनाएं शीत श्रृंखला अवसंरचना स्कीम के तहत, 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं (जिसे मिनी फूड पार्क भी कहा जाता है), एक बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज परियोजना और 15 खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) परियोजनाओं को असम राज्य में पीएमकेएसवाई के संबंधित घटकों के अंतर्गत अर्थात कुल 22 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाएं सीईएफपीपीसी योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 अनुमोदित किया गया है जिसका ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा आत्म निर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम एफएमई) योजना" की शुरुआत की है, जिसमें से 12778 यूनिटों को पांच वर्षों के लिए 638.92 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ असम राज्य को आवंटित किया गया है।

*****

संलग्नक

असम में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं 2343 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

असम राज्य में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं परियोजनाओं का सृजन/विस्तार

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जिला	अनुमोदित वित्त वर्ष	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	मेसर्स तिरुपति फूड्स	गुवाहाटी	2020-21	13.62	5.00	2.50	कार्यान्वयनाधीन
2	मेसर्स स्वास्तिक रोलर फ्लोर मिल	कामरूप	2020-21	18.22	5.00	0.00	कार्यान्वयनाधीन
3	मेसर्स सुभ करन फूड पार्क	कामरूप	2020-21	11.18	5.00	0.00	कार्यान्वयनाधीन
4	मेसर्स श्याम फूड्स	कामरूप	2020-21	2.59	0.71	0.00	कार्यान्वयनाधीन
5	मेसर्स राजा फूड एंड प्रोटीन्स	सोनितपुर	2020-21	6.25	2.05	0.00	कार्यान्वयनाधीन
6	मेसर्स शांति एग्रोवेट इंडस्ट्रीज	सोनितपुर	2020-21	11.3	4.62	0.00	कार्यान्वयनाधीन
7	मेसर्स इंपीरियल डेलीकेशियस	सोनितपुर	2020-21	13.28	5.00	0.00	कार्यान्वयनाधीन
8	मेसर्स सुभ करन फूड पार्क	कामरूप	2020-21	14.26	5.00	0.00	कार्यान्वयनाधीन
9	मेसर्स हर फूड्स एंड बेवरेजेज	नलबाड़ी	2020-21	10.93	4.97	0.00	कार्यान्वयनाधीन